



157

संक्षिप्त माननीय राजस्व मंडल मोप्र० ग्रालियर

अपील प्रकरण कमाक

/2016 जवलपुर

अ. - 1779 - I - 16

कमल सिंह पिता श्री पुन्न सिंह निवासी ग्राम
सिहोरा पोस्ट घाटपिपरिया थाना बंगी जिला
जवलपुर म.प्र.।

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर।
2. अटल उपाध्याय पिता श्री के.एल. उपाध्याय निवासी 1926/6 कजरवारा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.
3. राजेश उपाध्याय पिता श्री के.एल. उपाध्याय निवासी एस.एफ.आई. जवलपुर म.प्र.।

.....प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क 40/अ-21/2015-2016 मे पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

..... विरुद्ध के वातान्शो के

[Signature]

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1779—/1/2016

जिला—जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि- एंव आवेदक के हस्ताक्षर
२५-६-१६	<p>यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-05-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू- राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम मंगेली प.ह.न. 30 रा.नि. म. जवलपुर-2 तहसील व जिला जवलपुर जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 107 रकवा 0.740 है। उबड —खाबड होने एंव अन —उपजाउ होने से भूमि को विक्रय कर बच्चों की शिक्षा एंव पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 40/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन में अंकित तथ्यों की जाँच कराकर आदेश दिनांक 19.05.2016 पारित किया एंव अपीलांट का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण खारिज कर दिया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3— अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>4— अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार</p>	

करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 107 रकवा 0.740 है. के विक्य की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि उसके पास विक्य की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त 2.80 है. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विक्य की जाने वाली भूमि के विक्य उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एवं भूमि विक्य से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत वना सकेगा एवं अपनें बच्चों की शिक्षा एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकेगा। विक्य का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विक्य अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विक्य की जारही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्य की अनुमति मांगी गई है, एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्य की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य 2013 रा०नि०-०८-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू-राजस्व संहिता , 1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख)तथा 158 (3) का लागू होना -उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये –विना अनुमति के भूमि का अंतरण-उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया –उपबंध आकर्षित नहीं होते-भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन-का सिद्धात –नवीन उपबंध का अंतःस्थापन -भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया –ऐसे

PK

20

उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2) दयाली तथा एक अन्य विलद्द महिला श्यामबाई 2004 रानी 0183 में व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959 (मोप्र०) - धारा 165 (7-ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंतन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंजित किये - भूमि का विक्य कर सकता है - कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 40/अ-21/2015-16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्रम मंगोली प.ह.न. 30 (मानेगांव) रा.नि.म. जवलपुर-2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थित भूमि खसरा नं 107 रकवा 0.740 है 0 के विक्य की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- भूमि का क्य-विक्य के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2- भूमि का क्य-विक्य पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा।

3- केता द्वारा विक्य प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।



सदस्य

